



योगी बोल : विदेशी 07
सामान खरीदा तो...

राष्ट्रीय सिराज

खबरों की स्वतंत्रता

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र



सन ऑफ सरदार 2 11
की रिलीज होने पर...

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नई दिल्ली, देहरादून और लखनऊ से एक साथ प्रसारित

वर्ष - 01, अंक - 124

गाजियाबाद / बुधवार 06 अगस्त 2025

PRGI No. - UPHIN/25/A0086

पृष्ठ-12, मूल्य-04 रुपए



राज्यसभा में कमांडो बुलाने के विवाद पर फिर हँगामा

● खड़गे बोले- विरोध करना हमारा अधिकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद मानसून सत्र के 120वें दिन भी विपक्ष का बिहार वांटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर प्रदर्शन जारी रहा। लालकिंच और राज्यसभा को हांगामे के बाद 2 बजे तक थ्यूगिट कर दिया गया है। कांग्रेस



अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में 1 जूलाई को सीआईएसएफ कमांडो को बुलाने का विवाद सदन में उठाया। उहाँने कहा- विरोध करना हमारा अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। खड़गे ने उपसभापति हरिवंश नारायण से कहा- सदन में सीआईएसएफ लगाया गया था, इसलिए मैं पूछता चाहता हूँ कि इस आप चला रहे हैं या अपने शाह चला रहे हैं। इस पर हरिवंश सिंह ने कहा- सदन में सीआईएसएफ जवान नहीं मार्शल थे।

बिहार चुनाव से पहले जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह

● पटना हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक को दी जमानत

पटना (एजेंसी)। बिहार के बाहुली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह बिहार चुनाव से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे। पटना हाई कोर्ट ने आज मंगलवार को पूर्व विधायक अनंत सिंह को जमानत दे दी है। अनंत सिंह को चांपमहाना थाना कांड संख्या 5/2025 में जमानत मिली है। यह सोनू-मानू फायरिंग केस है। सोनू की मां ने पंचमहाना थाने में अनंत सिंह के चिनाफा एवं आइएसएफ अधिकारी दर्ज कराई थी। इस मामले में अनंत सिंह जेल से बाहर आ जाएंगे। पटना हाई कोर्ट ने जमानत जिले के बाद अब अनंत सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं। बैठ आईएसएफ की कौपी जेल प्रशासन को दी जाएगी। इसके बाद अनंत सिंह को रिहा कर दिया जाएगा। मामले में केस दर्ज होने के बाद अनंत सिंह ने खुद ही सर डर कर दिया था।

नीट यूजी काउंसलिंग 2025 पर लगाई गई रोक

● फर्स्ट राउंड की चॉइस

नई दिल्ली (एजेंसी)। मेडिकल काउंसलिंग कमीटी यानी एमसीटी ने 5 अगस्त को नीट यूजी 2025 के फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग फैसिलिटी को अस्थायी रूप से रोक दिया है। कमीटी ने इस रोक के लिए कोई कारण नहीं बताया है। एमसीटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग को रोक दिया गया है। रियाउंड शेड्यूल जल्द ही घोषित किया जाएगा। एमसीटी ने 21 जुलाई से नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के लिए इनस्ट्रेट्रॉन विडो और चॉइस फिलिंग फैसिलिटी को शुरू की थी। रिजल्ट आने के बाद, सिलेक्टेड फैसिलिटेस को 1 अगस्त से 6 अगस्त, 2025 के बीच अपने संबंधित संस्थानों को रिपोर्ट करना था।

प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में फिर भगदड़

● धरका-मुक्की में 2 लोगों की चली गई जान ● सीहोर में कांवड़ यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे



भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले स्थित पर्दीप मिश्रा के प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम में मंगलवार को भारी भीड़ के दौरान अफरा-तफरी मच गई। त्रिद्वालों को भारी भीड़ के कारण धबकामुक्की में दो लोगों को मौत हो गई, जबकि 8 से 10 लोग बेशर्ह ढोकर अस्पताल पहुंचे। इनमें से दो को हालत गंभीर बीमां हुई है। राजस्थान से भी बड़ी संख्या में त्रिद्वालु कुबेरेश्वर धाम पहुंचे हुए हैं। कुछ राजस्थानियों के भी धायल होने की सूचना है। हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्ट अपील नहीं की गई है। कथावाचक पर्दीप मिश्रा की

अटल पार्क, शास्त्री स्कूल, लुर्द मारा स्कूल और सीवन नदी के पास की गई थी। परे सबन मास प्रसारी वितरण की तैयारी भी की गई थी, लेकिन एक दिन पहले ही भीड़ का दबाव बढ़ने से व्यवस्था टूट गई। एसपी दोपक शुक्रवार ने बताया कि कांवड़ यात्रा के लिए 5 अगस्त तक जारी 12 बजे से 6 अगस्त रात 11 बजे तक अलग-अलग डायवर्जन और पार्किंग प्लान लागू होगा। भारी बाहों को बैकलिंग मार्ग से भेजने और छोटे बाहों को चूकिंसेट चौराहा से अमलाहा होते हुए भेजने की योजना थी। लेकिन हादसे के समय तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हुई थी।

पहाड़ से आया मलबा

देखते ही देखते गांव जर्मीदोज



के देखे होने की आशका जारी हो रही है। इस इलाके में बादल फटने से लोग घबराए हुए हैं। प्रशासन की तरफ से सभी लोगों के सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है और एहतियाती कटम उडाए जा रहे हैं ताकि कोई अनहोनी न हो। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कटम उडाए जा रहे हैं। हर तरफ पानी का सैलाब नजर आ रहा है। हाईविल क्षेत्र में खोर गड़ का जलस्तर बढ़ने से कम्बा धराली में भारी नक्सान हुआ है। पुलिस, एसडीआरएफ, राज्यव्यवस्था आर्मी और आदा लॉरी मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। कुछ ही मिनटों में, नाले में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा और पानी घरों में घुस गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इश्वर-उधर भागने लगे। कई



उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही डरा देंगी तस्वीरें

लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। बादल फटने की घटना से धराली गांव में भारी तबाही हुई है। कुछ घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और कई अन्य क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सड़कें और पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे गांव का संपर्क बाकी दुनिया से कट गया है। स्थानीय प्रशासन



और आपदा प्रबंधन टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रभावित लोगों को भेजन, पानी और आश्रय प्रदान किया जा रहा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सचिवार ने बादल फटने की घटना की ओर आदेश दिये हैं। अदेश जाता जा रहा है कि इस बाद में कीरीब 15 घर बह गए हैं। इसमें 10 लोगों के लापता होने की भी सूचना है। आर्मी और पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्य कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भराली से धराली के लिए निकल चुकी हैं, जबकि ऋषिकेश से अन्य टीमें भरात हो रही हैं। व्यवस्था के लिए भेजी गई है।

विपक्ष अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने में माहिर

● मोदी बोले- ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग करके गलती की

एनडीए सांसदों की हुई बैठक, प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया



लिप्ति रिविवान के मुद्रदे पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देश की जनता सब देख रही है। पीएम ने अमित शाह की भी तारीफ की और कहा कि वे अब सबसे लंबे समय तक सवा देने वाले कीरीब गढ़ मत्री हैं। एनडीए सांसदों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पास किया गया। इसमें कहा गया कि सैन्य शक्ति और मजबूत नेतृत्व के जरिए इसका हुआ भारतीय अतारकादाव को न तो भूला है, और न ही कभी माफ करता है। पीएम मंदिरी संसदीय दल की बैठक में एसडीए सांसदों से भी मिले बैठक में भाजपा और उसके सभी सहयोगी दलों के सभी सांसदों का शामिल होना अनिवार्य था। सांसदों को एक किताब दी गई।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन

● बिहार सहित 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, उनके कार्यकाल में हटा था आर्टिकल-370

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। उहाँने दोपहर 11.12 बजे संस ली। सत्यपाल मलिक लंबे समय से किंडी की बीमारी से जुझा रहे थे। 11 मई पर उहाँने अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे जम्मू-कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे। 2018 में ओडिशा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। सत्यपाल 23

अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक कार्यपाल के रूप में राज्यपाल रहे। इहाँ के कार्यकाल के दिन मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया था। उहाँने दोपहर 11.12 बजे संस ली। सत्यपाल मलिक लंबे समय से किंडी की बीमारी से जुझा रहे थे। 11 मई पर उहाँने अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे जम्मू-कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के र

द्वितीय पुण्यतिथि पर शत्-शत् नमन



(स्व. श्रीमती राधा रानी शर्मा)

(स्वर्गवास दिनांक 6 अगस्त 2023)

नैनं छिद्दन्ति शुल्क्राणि, नैनं दहति पावकः ।
न चौनं क्लेदयन्त्योपो, न शोषयति मारुतः ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय 2, श्लोक 23)

श्लोक अर्थः

इस आत्मा को शुल्क्र काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती,
पानी इसे गीला नहीं कर सकता, और वायु इसे सुखा नहीं सकती ।

भावार्थः

आत्मा शाश्वत है यह भौतिक साधनों से नष्ट नहीं होती
शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा अविनाशी है ।

४५
समस्त राष्ट्रीय शिखर परिवार

राष्ट्रीय शिखर

खबरों की स्वतंत्रता

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

४५

संपादकीय

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार : लोकतंत्र की दिशा में एक असहज लेकिन आवश्यक कदम

मंगलवार 5 अगस्त 2025 को संसद ने मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगामी छह महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दी, जो अब 13 अगस्त से प्रभावी रहेगा। इस निर्णय को सरकार ने संवैधानिक बाध्यता कहा। लेकिन इस विस्तारा ने एक बार फिर भारत में संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक परंपराओं को लेकर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। मणिपुर बीते दो वर्षों से जातीय हिंसा, प्रशासनिक पंगुता और कानून व्यवस्था की बिंगड़ीती स्थिति का प्रतीक बना हुआ है। मेझेटी और कुकी समुदायों के बीच उपजे संघर्ष ने न केवल राज्य की सामाजिक संरचना को तोड़ा बल्कि निर्वाचित सरकार की कार्यक्षमता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। हिंसा की चेपट में आए हजारों लोग अभी भी राहत शिखियों में जीवन बिता रहे हैं और सामान्य जीवन व्यवस्था बहाल होने की कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखती।

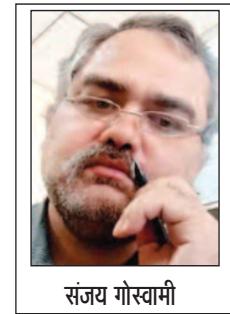
पिछले वर्ष राज्य में लागू हुए राष्ट्रपति शासन को अस्थायी समाधान मानते हुए स्वीकार किया गया था। उम्मीद थी कि छह महीने में हालात कुछ हद तक सुधरेंगे और लोकतात्त्विक प्रक्रियाओं की बहाली का मार्ग प्रशस्त होगा, लेकिन जमीनी हालात इसके ठीक उलट हैं। न्यायपालिका से लेकर मानवाधिकार आवेग तक, हर संस्थान ने मणिपुर में प्रशासनिक नियंत्रिता और राज्य की संवैधानिक विफलता को उजागर किया है और सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस पर तकरीबन 6 महीनों तक प्राथमिकी दज न करने का गंभीर आरोप लगाया और महिलाओं के खिलाफ हो रहा है। हिंसक घटनाओं पर कड़ी टिप्पणी की। ऐसे में सवाल यह नहीं है कि राष्ट्रपति शासन क्यों बढ़ाया गया, बल्कि यह है कि अब तक क्या किया गया और आगे क्या किया जाएगा? क्या यह केवल एक संवैधानिक जुगत है या केंद्र की ठोस रणनीति का हिस्सा? यदि केंद्र सरकार सचमुच राज्य में स्थिरता और शांति बहाली के लिए संकल्पित है, तो उसे प्रशासनिक ढांचे में सुधार, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और पुनर्वास कायें को पारदर्शिता से लागू करने के लिए अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करनी होगी।

लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। राष्ट्रपति शासन के लिए खिंचावाचक से लोकतात्त्विक दांचा कमज़ोर होता है। जब जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार की जगह एक निर्वाचित-न-होने वाला प्रशासन चलाता है, तो शासन की जवाबदेही भी कमज़ोर हो जाती है। क्या केंद्र यह भरोसा दिला पा रहा है कि छह महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे? क्या मणिपुर के लोग अपने भाग्य का निर्णय खुद करने की स्थिति में लौट पाएँगे?

सर्वधन अनुच्छेद 356 के तहत गणपति शासन का पावधान असाधारण

सावधान अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान असाधारण स्थितियों के लिए है, न कि शासन संचालन के सामान्य विकल्प के रूप में। मणिपुर में यह असाधारण स्थिति लम्बी होती जा रही है, और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। यह स्वीकार करने में कोइ संकोच नहीं कि राज्य सरकार की विफलता ने ही राष्ट्रपति शासन के अपरिहार्य बना दिया, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि यह अस्थार्थी समाधान एक स्थायी चलन न बन जाए। आज मणिपुर की सबसे बड़ी जरूरत है विश्वास। यह विश्वास कि देश का सर्वधान उन्हें सुरक्षा देगा न्याय देगा और उनके जीवन को फिर से सामान्य बनाएगा। लेकिन यह विश्वास तब टूटा है जब राहत शिविरों में रहने वाले लोग महीनों से अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हों, जब अपराधी खुलेआम घूम रहे हों और जब राज्य की पुलिस तक निष्क्रिय बनी रहे।

~  मौलिक चिंतन  ~
कमियाँ सभी में होती हैं, लेकिन किसी में अच्छाई ढूँढ़ना
वास्तविक कला है।



संजय गास्त्राम

आँ परेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को सबक भारतीय सेनाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को सुरक्षित किया इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इसे राजनीति के विट्टकोण के नजरिया से नहीं बल्कि देश का सेप्टेम्बर अमिल तर्फेंटी राजनीति के देश का सम्बिलण

हित मे देखना चाहिए क्योंकि उनकी हमेशा मानसिकता देश को बचाने की होती है और सेना का मनोबल हर उस देश का राष्ट्रपति सेना को उनकी बहादुरी पर सम्मान करता है इसे आप कितनी बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलरेस्की ने रूस से लड़ने वाले सेनाओं का सम्मान किया है ऐ अलग बात है भारत को इससे लेना देना नहीं है लेकिन यहाँ के यूट्बर्ब्स और कुछ मीडिया चैनलों पर देश में ऑपरेशन सिंटूर को लेकर सियासत करते नजर आते हैं लेकिन सेना के पराक्रम को नजरअंदाज कर देते हैं इसका फायदा शत्रु देश उठाते हैं और भारत माता के प्रति अपनी नकारात्मक छवि को दर्शाते हैं यू टुब बना कर मीडिया में दिखाना बहुत आसान है हम भी बना लेंगे और डाउनलोड कर देंगे लेकिन इसपर सेना के प्रवक्ता ने जब सब कुछ खुल कर बता दिए हैं कि हम तीन मोर्चों पर पाकिस्तान से लड़ रहे थे और नुकसान भी हुआ लेकिन जो टारगेट था उसे प्राप्त किया है तो ऐसे में खुद यू टुब बनाकर डालना बचकाना हरकत होगा और लोगों में गलत धारना पैदा होगा सेना का मनोबल गिरेगा याद होगा कारणिल का युद्ध जिसमें पाकिस्तान द्वारा धोखे



राजश कुमार स

कुछ दिन पहले का है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने घर से दफ्तर जाने के क्रम में सुवह-सुवह जाम का शिकार हो गई, तब उन्हें अहसास हुआ कि विकास को लेकर दिल्ली की इमेज को सबसे ज्यादा नुकसान जाम के कारण हो रहा है। ठीक इन्हीं दिनों एक महज संयोग है कि केंद्र सरकार ने भी दिल्ली की सीमा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम के लिए एमसीडी टोल प्लाजा को जिम्मेदार ठहराते हुए, इन्हें हटाने को कहा। केंद्र ने सुशांत विद्या है कि इन टोल से एमसीडी को होने वाले राजस्व की भरपाई दिल्ली सरकार अपने दूसरे संसाधनों से करे। मसलन यूपी से रोजाना दिल्ली आने वाले हजारों लोगों को लगा कि जल्द ही जाम से छुटकारा मिलने वाला है। क्योंकि एन एच-9 समेत कई एमसीडी टोल बूथ को हटाने की तैयारी चल रही है। इसके हटने के बाद यहाँ ट्रैफिक जाम से निजात मिल सकती है। बड़े शहरों में सड़क जाम कोई हालिया समस्या नहीं है। अब दिल्ली की सीमाओं पर लगी लंबी कतारों के लिए दिल्ली सरकार और एमसीडी जैसी एजेंसियों ने व्यावसायिक वाहनों से प्रवेश शुल्क वसूलने के लिए



टैरिफ दादागिरी के बीच 'स्वदेशी' एक जनक्रांति बने

वा राणसी में अपने लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे संकल्प लें कि अपने घर स्वदेर्शन सामान ही लाएं। उनका यह आह्वान न केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'दबाव की राजनीति' और 'टैरिक कर्म दादागिरी' का माकूल जबाब है बल्कि भारत को सशर्त अर्थ-व्यवस्था बनाने की बुनियाद भी है। मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' का आह्वान इसी सोच के साथ किया है उन्होंने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि भारत को 'लोकलेस के लिए वोकल' बनाना होगा। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक गहन आर्थिक और सांस्कृतिक रणनीति है जो हमें बाहरी निर्भरता से मुक्त कर सकती है। यह वर्द्धा आत्मनिर्भरता है, जिसका बोजारोपण महात्मा गांधी ने चरखें और खादी के माध्यम से किया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वदेशी जागरण के माध्यम से कर रहा है। दोनों दोनों तरीं तौर पर एक ही परिस्थिति है कि उन्होंने



पुनरुत्थान किया है, वह अनेक विकसित देशों के लिए उदाहरण है। सच्चाई यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था तो मृत है, न ही दिशाहीन। हाँ, चुनौतियाँ हैं, बेरेजगां महांगाई, आय असमानता, लेकिन इनसे जूँझते हूँ प्रभाव आत्मनिर्भरता और नवाचार की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठा रहा है। वैश्विक मंचों पर भारत की वाणी अब कमज़ो नहीं, बल्कि दृढ़ता और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। ऐसमय में जब अमेरिका जैसे देश एकत्रफा फैसलों वैश्विक व्यापार संतुलन को तोड़ने पर आमादा हैं, तभारत को अपनी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के मंत्र को एसंकल्प बनाकर व्यवहार में लाना होगा। अमेरिका हो चीन, अर्थिक नीतियों में नैतिकता नहीं, स्वार्थ ही केंद्र रहता है। इसीलिए भारत को अब यह समझना होगा कि केवल आयात पर निर्भर रहकर हम अपनी आर्थिक सुरक्षा नहीं कर सकते। जब तक हम उत्पादन, निर्माण और उपभोग के क्षेत्र में स्वदेशी विकल्प नहीं अपनाते, तब तक हम इस टैरिफ आतंकवाद और वैश्विक अस्थिरता के दिक्कतों से बच सकते। यह बात दोहराते रहे हैं कि भारत व आर्थिक समझौता का मूल मंत्र 'स्वदेशी' है। यह विचार केवल देसी वस्तुओं के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है, स्वदेशी संसाधनों, तकनीकों, कौशल और संस्कृति के आधार पर विकास का रास्ता तय करना। भारत का आर्थिक इतिहास इसका साक्षी है कि जब-जब देश अपनी आंतरिक क्षमताओं पर विश्वास किया, तब-तब उसने वैश्विक मंच पर अपना प्रभुत्व सिद्ध किया। चाहे दू

उत्पादन में श्वेत क्रांति हो, अंतरिक्ष में इसरो की सफलता हों या कोविड काल में स्वदेशी वैक्सीन बनाना, भारत दिखाया है कि वह किसी से कम नहीं है। स्वदेशी का सिर्फ 'यहां बनाएँ' तक सीमित नहीं है, यह 'यहां के लोगों द्वारा, यहां की सोच के साथ' बनाया गया भारत प्रधानमंत्री मोदी का 'मेक इन इंडिया' अभियान अब 'मेक बाय इंडिया' की दिशा में अग्रसर हो रहा है। भारत को ऐसी आर्थिक संरचना बनानी होगी जिसमें विदेशी पूँजी तकनीक की बजाय स्वदेशी नवाचार, स्वदेशी उद्योग, अस्वदेशी उद्यमिता को बल मिले। इस संदर्भ में सरकार भी यह सुनिश्चित करना होगा कि जो नीतियां बनें, वे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने वाली हों, न कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लौंगी के दबाव में चलने वाली। आज का समय यै ही है जैसा 1905 में बंग-भंग आंदोलन के समय था, जब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद चौधरी जैसे क्रांतिकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। आज फिर एक नई क्रांति की जरूरत है, लेकिन यह क्रांति फैक्ट्रीयों में, बाजारों में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाजाएंगी। हमारे युवाओं को चाहिए कि वे स्टार्टअप्स इनोवेशन और तकनीकी प्रयोगों में विदेशी नकल न वाले बल्कि भारतीय जरूरतों और मूल्यों के अनुरूप समाधान विकसित करें। यही आत्मनिर्भर भारत की आपात्कालीन विदेशी उत्पादन बनाना होगा कि जब वह विदेशी युद्धों में जीत ले रहा है।

अब समय है कि उपभोक्ता भी जिम्मेदार बने। स्वदेशी उपभोग सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि देशभक्ति का आधुनिक रूप है। आज जब वैश्विक पूँजीवाद लड़खड़ा रहा है और पश्चिमी देशों की नीतियों में आत्मकोदितत हावी हो रही है, भारत को अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक और बौद्धिक जड़ों की ओर लौटना ही होगा। यही समय है जब 'स्वदेशी' एक आदोलन बने, एक जनक्रांति बने और एक ऐसी नई अर्थव्यवस्था की नींव डाले जो टिकाऊ, समावेशी और पूर्णतः आत्मनिर्भर हो। प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्वदेशी का दीप जलाया है, वह केवल सरकार का काम नहीं, वह हम सभी का नैतिक, राष्ट्रीय और आत्मिक दायित्व है। तभी हम न केवल ट्रूप जैसी टैरिफ दावागिरी का जवाब दे पाएंगे, बल्कि एक सशक्त, सम्मानित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकेंगे, अपने स्वेद, अपने स्वप्न और अपने स्वदेश के बल पर। वर्तमान परिवेशों में यह आवश्यक हो गया है कि देश की आलोचना के नाम पर विदेशी अपमान का समर्थन करने की प्रवृत्ति का जननात्मिक रूप से विरोध हो। लोकतंत्र की सच्ची परिपक्वता यही है कि सरकार की आलोचना करते हुए भी हम राष्ट्र की प्रतिष्ठा और आत्मगौरव की रक्षा करें। जब तक भारत के भीतर से ही भारत की आवाज कमज़ोर की जाएगी, तब तक ट्रूप जैसे बाहरी 'टैरिफ तानाशाहों' को हमारे आत्मबल पर वार करने का साहस मिलता रहेगा। यदि हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी तो फिर कोई वैश्विक नेता दबाव बनाकर हमारी विदेश व आर्थिक नीतियों को प्रभावित न कर सकेगा। विडंबना यह है कि चीन के लगातार शुरुतापूर्ण व्यवहार व सीमा पर तनाव के बावजूद चीनी उत्पादों का आयात बढ़ता ही जा रहा है। यहां तक कि हमारे त्योहारों का सामान भी चीन से बनकर आ रहा है। जरूरत इस बात की भी है कि हम अपने विश्वाल असंगठित क्षेत्रों को संगठित क्षेत्र में शामिल करने के लिये प्रयास करें। हम यद खेलें कि चीन ने अपने देश में लघु उद्योगों को संगठित करके ही दुनिया में उत्पादन के क्षेत्र में बादशाहत हासिल की है। विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत को अपनी युवा आबादी की क्षमता का उपयोग करने के लिये इस दिशा में बड़ी पहल करनी होगी। हमारा शिक्षा का ढांचा इस तरह तैयार हो कि हम कौशल विकास को अपनी प्राथमिकता बनाएं। जिससे हम कालांतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीक का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिये कर सकें। तब स्वदेशी के संकल्प से भारत न केवल आत्मनिर्भर होगा, बल्कि हम गुणवत्तापूर्ण निर्यात के जरिये अपने दुर्लभ विदेशी मुद्रा भंडार को भी समृद्ध कर सकेंगे।

